



राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उसके कार्यक्रमों और नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन सरकार के लिए रोजगार की स्थिति अब भी बड़ी चुनौती है।

चुनाव से पहले

राष्ट्रपति

रामनाथ कोविंद ने सोलहवीं लोकसभा के अपने आखिरी अधिभाषण में मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए आश्चर्य किया है कि देश आर्थिक विकास की राह पर है। यह अधिभाषण इसलिए अहम है, क्योंकि दो महीने बाद आम चुनाव हैं, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। राष्ट्रपति ने खासतौर से जन धन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और मुद्रा सहित ईस्टर्न पैरिफेरल रोड जैसी अनेक आधारभूत संरचनाओं का जिक्र किया है, जिनकी वजह से जमीनी स्तर पर बदलाव देखा जा सकता है। राष्ट्रपति ने आधार का जिक्र नहीं किया, पर पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण ने मनरेगा जैसे सांविधानिक रूप से बंधे कार्यक्रम

में व्यापक बदलाव लाया है। मोदी सरकार नवंबर, 2016 की नोटबंदी और जीएसटी को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है और दावा करती आई है कि इनके जरिये समानांतर अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने में मदद मिली है और कर व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। यही नहीं, जैसा कि राष्ट्रपति ने भी उल्लेख किया कि सरकार ने सत्ता में आते ही काले धन और भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी गठित कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। हालांकि अनेक अर्थशास्त्रियों ने नोटबंदी को कारण नहीं बताया था और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 के दौरान बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी रही थी। मोदी सरकार ने मौजूदा सीमा को लंघिते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने की

पहल की है, पर नए रोजगारों का सृजन एक बड़ी चुनौती है, और सात फीसदी से अधिक की विकास दर के बावजूद रोजगार पैदा नहीं हो सका। इसी तरह से आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने और खुशोटा कंपनियों के लाखों खातों को सील करने के बावजूद सरकार लोकपाल के गठन में विफल रही है। राष्ट्रपति ने तीन तलाक विधेयक का जिक्र करते हुए मुस्लिम महिलाओं के हितों को लेकर सरकार की चिंता को जाहिर किया है। पर यह विधेयक अभी राज्यसभा में अटका है और इसे पारित करवाना बड़ी चुनौती है। यही स्थिति नागरिकता विधेयक की है, जिसे लेकर पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो इस सत्र में अंतरिम बजट पेश होना है, लेकिन सरकार चुनाव में जाने से पहले इस मौके का लाभ उठाना चाहेगी।

अंतर्ध्वनि
>> मरीना त्सेतायेवा

बच्चे की तरह मेरी भावनाओं में कोई हद नहीं है

आत्माओं की पूर्ण सहमति के लिए सांसों के समन्वय की जरूरत है, क्योंकि सांस आत्मा की लय होती है। इस तरह जो लोग एक दूसरे को समझते हैं, उन्हें साथ में टहलना और पास-पास लेंटे रहना चाहिए। मैं कह सकती हूँ: मेरा दिल प्रेम से नहीं धड़कता, बल्कि मेरा धड़कता हुआ हृदय— प्रेम का कारण है। हृदय: शरीर का अंग होने के बजाय संगीतमय है। हृदय गूँजन वाली लकीर, बौद्धि, लट्टा, शक्तिमापक, तापमापक— यह सब कुछ होने के साथ-साथ प्रेम की

सही वक्त बताने वाली घड़ी है। आप दो व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, इसलिए आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे द्वारा दो व्यक्तियों को प्रेम करना संभव होने के लिए यह जरूरी है कि उनमें से एक का जन्म मुझसे सौ साल पहले हो चुका हो या कभी हुआ ही न हो (मसलन एक तस्वीर, एक कविता)। यह एक एक ऐसी शर्त है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है।

‘प्रियतम’ नाटक की है, ‘प्रेमी’ बिदास है, ‘दोस्त’ अस्पष्ट है। हमारा देश प्रेमियों के लिए नहीं है। प्यार की पहली झलक दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी है, वह दिव्य सीधी रेखा, जिसके बाद कोई और रेखा नहीं है।

बच्चे की तरह मेरी भावनाओं में कोई हद नहीं है। किसी आदमी पर औरत की पहली फतह आदमी की किसी और के लिए प्रेम-कहानी होती है। मगर उसकी अंतिम विजय किसी और औरत द्वारा उस आदमी के लिए प्रेम और आदमी के उसके प्रति प्रेम की कथा होती है। जो राज था, वह उज्जगर हो जाता है, तुम्हारा प्यार मेरा हो जाता है और जब तक वह नहीं होता है, तुम चैन से सो नहीं सकते हो। जो कुछ भी बताया नहीं जाता है, टूटने से बचा रहता है।

-रूसी साहित्यकार

पाकिस्तान इन दिनों शांति और सुलह प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रहा है, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि तालिबान अमेरिकियों और राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार से बात करें। पाकिस्तान के लिए तालिबान को दोहा में वार्ता की मेज तक पहुंचाना आसान नहीं था। इसका कारण यह है कि तालिबान का अफगानिस्तान के भीतर एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण है, वे उस देश के गरीब, युद्ध पीड़ित जनता पर आतंकवादी हमले कर रहे हैं और दुनिया के हर देश की राजधानी उनसे बात करने के लिए पहुंच रही है।

अब तालिबान न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि वार्ता की मेज पर भी मजबूत हैं, और इस पर उनका पूर्ण नियंत्रण है कि भविष्य में शांति और सुलह प्रक्रिया कैसे जारी रहेगी। मैं इसे ‘सतर्क आशावाद’ कहना चाहूँगी, क्योंकि अतीत में भी तालिबान शांति वार्ता के काफी करीब आ चुके थे और फिर अपने ही देश में विनाश जारी रखा। तो सवाल उठता है कि क्या इस बार उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए।

एक संकेत है कि तालिबान अपने हथियार डाल सकते हैं और अंततः सुलह का रास्ता अपना सकते हैं। उन्होंने हाल ही में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की नियुक्ति की घोषणा की है, जो तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे विश्वासपात्र थे, जब 1993 में आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ वर्ष पहले वह पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान को भरोसे में लिए बिना अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हमिद करजई और अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की थी। वह तालिबान के क्षेत्रीय कमांडरों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और यदि कोई निर्णय लिया जाना है,



अब जब दुनिया भर की राजधानियों में एक बार फिर अफगानिस्तान में आतंक का खेल खत्म होने की चर्चा हो रही है, तब मुझे सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या सचमुच वहां हिंसा खत्म होने वाली है।

मरिआना बाबर, पाकिस्तानी पत्रकार



तो मुल्ला बरादर अनेक कमांडरों को अपने हथियार रखने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होंगे। हालांकि तालिबान के भीतर भी विभाजन है।

अब तक एक चीज जो मालूम नहीं है, वह यह है कि क्या तालिबान को राष्ट्रपति अशरफ गनी या उनके प्रतिनिधियों के साथ मेज के चारों ओर बैठने के लिए आश्चर्य किया जा सकता है। बरादर सभी अफगानों से बात करने के लिए जाने जाते हैं और

उम्मीद है कि उनका सबसे बड़ा योगदान सभी अफगानों को बातचीत में शामिल करना है।

पाकिस्तान की एक छोटी-सी जीत तब हुई, जब तालिबान और अमेरिकी मुख्य वार्ताकार राजदूत जलमय खलीजाद के बीच समझौते के मसौदे में तालिबान ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य में अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी अन्य देश पर हमले शुरू करने के लिए नहीं किया जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए अहम है, क्योंकि आतंकवादी

संगठन टीटीपी यानी पाकिस्तान तालिबान सुरक्षित अय्यारण्यों के साथ अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, जहां से वह पाकिस्तान के भीतर हमले करता है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकी हमले को, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चे मारे गए, टीटीपी ने ही अंजाम दिया था।

लेकिन आज अगर अफगानिस्तान में किसी भी तरह की शांति लौटती है, तो सभी पड़ोसी देशों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि इस्लामिक स्टेट को वहां जगह नहीं मिलेगी। अंग्रेजी दैनिक डॉन का कहना है, इस्लामिक स्टेट के बढ़ते खतरों के मद्देनजर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में खफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना जरूरी है। इस्लामिक स्टेट का खतरा ऐसा खतरा है, जो किसी भी सीमा का सम्मान नहीं करता। उत्तरी क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य अभियान का लाभ तभी तक है, जब तक हिंसक चरमपंथी को सीमा के किसी भी तरफ छिपने की जगह नहीं मिलेगी।

एक और चिंता की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की जल्दी है, जो तालिबान की एक प्रमुख मांग है। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक जाहिद हुसेन कहते हैं, फिर अफगानिस्तान में गैर-हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले क्षेत्रीय समझौते की भी आवश्यकता है। क्षेत्रीय देशों को अफगानिस्तान में गृहयुद्धों को बढ़ावा दिया है। हालांकि एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, लेकिन काबुल में शांति आसान नहीं है। अगर अमेरिकी सैनिक वापस बुला लिए जाते हैं और तालिबान एवं काबुल सरकार अफगानिस्तान में शांति कायम नहीं कर पाती है, तो पाकिस्तान को चिंता है कि एक बार फिर अफगान शरणार्थी और आतंकवादी पाकिस्तान आएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तुनख्वा और

अफगानिस्तान से लगी बलूचिस्तान सीमा पर कोंटेदार बाड़ लगा रही है, ताकि सीमापार से घुसपैठियों को रोका जा सके।

पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र अफगान तालिबान के लिए सुरक्षित पनाहगाह था और सैन्य अभियान से पहले पाकिस्तान तालिबान यहां रहते थे और सैन्य अभियानों के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाके में शांति बहाल हो पाई। इस बात का डर है कि जब अमेरिकी सेना वापस चली जाएगी और अफगानिस्तान में गृहयुद्ध शुरू होंगे, तो एक बार फिर आतंकी संगठन पाकिस्तान के कबायली इलाकों में आने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर कहती और लिखती रही हूँ कि पाकिस्तान समेत सभी क्षेत्रीय देशों के लिए शांति का आव्हान करना आसान है, लेकिन असली सवाल यह है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में दखल देना बंद कर देंगे, तो क्या होगा।

ऐसा कोई देश नहीं है, जिसका अफगानिस्तान में अपना हित न हो। सभी देश वहां अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। यह वास्तव में अफगानों के लिए मिलकर अपने देश और अपने लोगों के भविष्य के बारे में बात करने का वक्त है। चाहे वहां काबुल सरकार हो या तालिबान उसके साथ सत्ता में बैठे, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भावी शांति और सुलह प्रक्रिया उनके अपने लोगों के लिए हो, न कि पड़ोसी देशों के हित में।

अफगान दूसरों को दखल देने की अनुमति देने के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं, ताकि वे अफगानिस्तान के भीतर ज्यादा मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभर सकें। यदि एक बदलाव के लिए भविष्य की शांति योजना खुद अफगानिस्तान के लोगों की ओर से आती है, तो यह रणनीति सफल होगी।

अफगान जियो और जीने दो में भरोसा करेंगे या नहीं, इसका पता जल्द चल जाएगा।

मंजिलें और भी हैं
>> रुचिरा गुप्ता

अंधेरी गलियों में शिक्षा का उजाला

स्टोरी के सिलसिले में मैं नेपाल के एक गांव में थी। मुझे गांव में लड़कियों की संख्या कुछ कम दिखी, सो मैंने वहां लोगों से इसका कारण पूछा। मुझे सीधा जवाब तो नहीं मिला, लेकिन यह पता चल गया कि इसके पीछे आखिर वजह क्या थी। दरअसल वहां की लड़कियां एक बनी-बनाई व्यवस्था के तहत मुंबई की बदनाम गलियों में भेज दी जाती थीं। मानव तस्करी का वह खेल लंबे समय से अनवरत जारी था, जिसमें काम आते थे, गांव के कुछ लालची लोग, भ्रष्ट सीमा प्रहरी और तमाम आपराधिक रचेरे वाले लोग। इस नई जानकारी से पहले मैंने पत्रकारिता करते हुए युद्ध, महिला और गरीबी जैसे मुद्दों को कवर किया था, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। मैंने बंगाल और दिल्ली के नामी मीडिया संस्थानों में काम किया है। इस दौरान मैंने अल्पसंख्यकों के मुद्दों और पूर्वोत्तर भारत की जरूरतों पर खूब लिखा। मैंने नेपाल की उस आसन्न स्थिति को डाक्यूमेंटरी के जरिये दिखाने की कोशिश की। *द सेलिंग ऑफ इन्वॉयंट्स* नामक उस फिल्म के लिए मुझे पुरस्कार भी मिला। लेकिन पता नहीं क्यों, वह पुरस्कार लेकर मुझे मजा नहीं आया। क्योंकि फिल्म देखकर लोग भावुक तो हो रहे थे, पर उन बच्चियों की सुरक्षा का कोई बंदोबस्त हुआ नहीं, जो कि मेरा मुख्य उद्देश्य था। डाक्यूमेंटरी शूट करते वक्त मैं वेश्यालयों में भी गई थी। वहां मुझे कई अच्छी सहेलियां मिलीं। मैंने अपनी सखियों के दर्द, आंसू और दुखों को बहुत करीब से महसूस किया। इन एहसासों ने मुझे दोबारा पत्रकारिता में वापस आने से रोक दिया और मैंने वह क्षेत्र छोड़कर ‘अपने आप’ नाम से एक संस्था की स्थापना की। संस्था की स्थापना के पीछे मेरा प्राथमिक उद्देश्य यह था कि मैं अपने सहयोगियों की मदद से इन बदनाम गलियों में जाकर वहां रह रही महिलाओं से बात करूँगी। उन्हें अपनी संस्था से जुड़ने का प्रस्ताव दूँगी, और यदि वे हां करती हैं, तो उन्हें बाकायदा परिचय पत्र देकर अपने दफ्तर आने को कहूँगी। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। जब वे औरतें हमसे जुड़ने लगीं, तो हमने उनकी समस्याओं और उनकी इच्छाओं पर बात की। हमने उनके समूह बनाए और उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने के तमाम तरीकों से अवगत कराया। हम उनको कई ऐसी सरकारी योजनाओं के दायरे में लेकर आए, जिसके बारे में उन्हें पहले अंदाजा ही नहीं था। उन महिलाओं ने अपनी बेटियों को भी उस दलदल से निकालने की कोशिशें शुरू कर दीं। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से होने वाला नहीं था। वेश्यालय के प्रबंधकों ने उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। हमने प्रताड़ित महिलाओं की कानूनी मदद भी की। सोलह साल से भी ज्यादा समय से मेरी संस्था ऐसी ही महिलाओं की मदद कर रही है। हमने इन महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा के लिए भी काम किए हैं। दूसरी बात यह कि हमने उनके लिए खुद के घरों का भी इंतजाम किया है, ताकि उन्हें दूसरों के आसरे में रहकर जल्म न सहने पड़ें। हाल ही मैंने इन इलाकों में रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए एक मोबाइल लाइब्रेरी की भी शुरुआत की है, जिसके बहुत सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि किसी भी महिला के लिए इस तरह के काम करने के लिए हां कहना सबसे आखिरी विकल्प होता है।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

अंतरिम बजट से उम्मीदें

सरकार ने संकेत दिया है कि वह सिर्फ लेखानुदान पेश नहीं करेगी, बल्कि देश की आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु भी नीतिगत दिशाएं भी देगी। उम्मीद है कि अंतरिम बजट में विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त रियायतें दी जाएंगी।



जयंतीलाल भंडारी

पूरे देश के लोगों की निगाहें आज 2019-20 के अंतरिम बजट की ओर लगी हुई हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि अंतरिम बजट में सिर्फ चार महीने के लिए लेखानुदान पेश नहीं किया जाएगा, वरन देश की आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत दिशाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। सरकार का आखिरी बजट होने के कारण इसे लोक लुभावन बनाए जाने की संभावना है। सरकार करीब 26 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश कर सकती है। पिछले बजट का आकार 24.42 लाख करोड़ रुपये था। अंतरिम बजट के आकार के संबंध में संविधान के प्रावधान मौन हैं। ऐसी कोई कानूनी या सांविधानिक बाधा नहीं है, जो सरकार को चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश करते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों में संशोधन करने का प्रस्ताव करने से रोकें। अब तक केंद्र की विभिन्न सरकारों द्वारा परंपरा तोड़ने वाले कुछ अंतरिम बजट पेश भी किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि आठ फीसदी विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए अंतरिम बजट में रणनीति पेश करना जरूरी है। हालांकि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के करीब 3.3 फीसदी पर केंद्रित है। ऐसे अनुकूल परिवेश में सरकार सीमा शुल्क सहित आयात संबंधी बदलाव के साथ विभिन्न वर्गों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए उठाए जाने वाले कदमों को रेखांकित करते हुए दिखाई देगी।

यह बजट मुख्यतः खेती और किसानों को लाभान्वित करते हुए दिखाई दे सकता है। सरकार

बजट में नकद के रूप में राहत देने के लिए ऐसी योजना प्रस्तुत कर सकती है, जिसके तहत किसानों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए सब्सिडी की जगह सीधे उनके खातों में नकद रकम ट्रांसफर की जाएगी। सरकार खेती-बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की सब्सिडी को जोड़ने की एक योजना पेश कर सकती है, जिसमें करीब 70 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था जरूरी होगी। कृषि कर्ज का लक्ष्य 10 फीसदी बढ़ाकर करीब 12 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है। देश के सभी गरीब परिवारों को न्यूनतम आय की गारंटी दी जा सकती है। असमानता और गरीबी की चुनौती से निपटने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इन्कम (यूबीआई) की जरूरत महसूस की जा रही है। छोटे

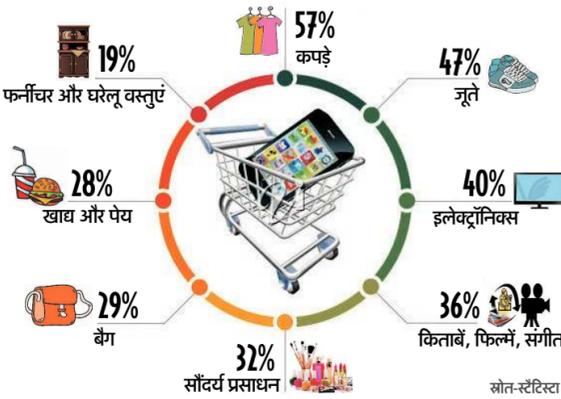
खुली खिड़की

ऑनलाइन खरीदारी के वैश्विक रुझान

भारत में भले ही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं पहली पसंद हो, लेकिन वैश्विक रुझानों में फेशन से जुड़ी चीजें सबसे ऊपर हैं। साल 2018 में दुनिया के सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में सर्वाधिक 57 फीसदी लोगों ने ऑनलाइन कपड़े खरीदे।

विभिन्न ई-कॉमर्स माध्यमों से खरीदारी के वैश्विक रुझान

आंकड़े- कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों में की गई खरीदारी



सत्संग

हो गया है। मुझसे कोई बात तक नहीं करता। मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं पापी हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। नानक देव जी बोलीं, नीच तो वे लोग हैं, जिन्होंने तुम पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। मेरे पास आओ। वह आदमी जैसे ही नानक देव जी के नजदीक आया, उसका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। वह उनके चरणों में गिर गया। नानक देव जी ने उस गले से लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण और लोगों की सेवा करो। यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है।

-संकलित।

हरियाली और रास्ता

मनन और वह बूढ़ा आदमी

एक बुजुर्ग की कहानी, जो बताती है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है।



मनन अपने ऑफिस से निकला ही था कि उसे जोर की भूख लगी। उसने रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोकी और बर्गर व कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। जब तक उसका ऑर्डर आता, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दुकान के ठीक बाहर पड़े एक बड़े-से कूड़ेदान को टटोल रहा था। जिज्ञासावश मनन कूड़ेदान के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति कूड़ेदान से एक-एक लिफाफा निकाल कर खाने के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। मनन का बर्गर पैक हो गया, तो वह अपनी गाड़ी में बैठ गया। पर उसकी नजरें अब भी बूढ़े पर ही थीं। बूढ़े ने अब इकट्ठा किया गया खाद्य पदार्थ रूमाल में बिछा लिया और वहीं बैठकर खाने लगा। यह देखकर मनन को गुस्सा आ गया। गाड़ी से बाहर निकल कर वह उस बूढ़े से कहने लगा, क्यों, रे, गंदगी फैलाने के लिए तुझे और कोई जगह नहीं मिली थी? मनन को गुस्सा होते देखकर दुकान का मैनेजर और सुरक्षा कर्मी भी वहां आ गए। मनन ने उनसे कहा, आप लोग ऐसे भिखारियों को अपनी दुकान के सामने बैठने कैसे देते हैं? मैनेजर बोला, माफ कीजिएगा, यह आदमी भिखारी नहीं है। आपको गलतफहमी है। मनन हैरान था कि मैनेजर मनन की तरफदारी करने के बजाय उस बूढ़े का पक्ष ले रहा है। तभी वह बूढ़ा आदमी उठा और मनन से कहने लगा, अगर आपको बुरा लगा हो, तो माफ कीजिएगा। आपको पता नहीं कि यह दुकान कभी मेरी ही थी। लेकिन बूढ़े होने पर मैंने इसे अपने बेटे के नाम कर दिया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मुझे कैसर हो गया है। कैसर का पता चलते ही मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस दुकान ने जिंदगी भर मेरा पेट भरा है, आज भी मैं इसी के सहारे जिंदा हूँ। मनन कुछ दूर के लिए उस आदमी को स्तब्ध खड़ा देखता रहा।

समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए।